भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4106
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार की सुविधाएं

†4106. श्री टी.आर. बालू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रचालनशील रणनीति कच्चे तेल के भंडारों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी के अप्रत्याशित झटकों से तेल उद्योग को बचाने में मदद की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संकट की अवधि के दौरान मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), सुपर केरोसीन ऑयल (एसकेओ), एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों का प्रबंधन किस प्रकार किया जा रहा है;
(घ) क्या सरकार की ऐसे और कच्चे तेल के भंडारों का सृजन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) : सरकार ने इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाली कंपनी के माध्यम से स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) सुविधाएं 3 स्थानों अर्थात (i) विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), (ii) मंगलुरु (1.5 एमएमटी) और (iii) पादुर (2.5 एमएमटी) पर स्थापित की हैं, जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की है।

(ख): सरकार, उभरती भू-राजनैतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में वैश्विक उर्जा बाजारों की परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखे हुए है तथा बाजार संबंधी अस्थिरता को कम करने के लिए जैसी उचित हो, सभी यथाउपयुक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

(ग): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के 85% से अधिक का आयात करता है। कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) के मूल्य 55 डॉलर/बीबीएल (मार्च 2015) से बढ़कर 113 डॉलर/बीबीएल (मार्च 2022) और उससे अधिक बढ़ कर 116 डॉलर/बीबीएल (जून 2022) हो गया है और यह लगातार अत्यधिक अस्थिर बने हुए हैं। सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरुप, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करना तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य वैट दरों को कम करना शामिल है, आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को राहत प्रदान की गई है।

भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित करती रहती है।

वर्तमान में, सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति सिलिंडर 300 रुपए की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से भी अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को सीधे राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अंतरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पर न डालने के कारण उन्हें होने वाली अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

दिनांक 01 मार्च, 2020 से पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य अखिल भारतीय आधारों पर अल्प-वसूली स्तर पर शून्य रखे जा रहे हैं।

(घ) और (ड.): सरकार ने जुलाई 2021 में ओडिशा के चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर (2.5 एमएमटी) में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त वाणिज्य-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है।

*****